

भारत का प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

1623. श्री अजीत जोशी :

श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या "अग्नि" और अन्य प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान और चीन द्वारा तैनात किए गए प्रक्षेपास्त्रों की तुलना में अधिक कारगर साबित होंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : "अग्नि" केवल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रक्षेपास्त्र है जो इस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी सुविज्ञता और पुनःप्रवेक्ष प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रमाण है। देश में ही विकसित किए जा रहे "पृथ्वी", "आकाश", "त्रिशूल" तथा "नाग" प्रक्षेपास्त्र किसी अन्य देश के इस श्रेणी के इस समय के प्रक्षेपास्त्रों के मुकाबले के होंगे।

भोपाल में दूरदर्शन केन्द्र का प्रारंभ न किया जाना

1624. श्री अजीत जोशी :

श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सम्पूर्ण तैयारी हो जाने के बाद भी, केवल शिथिलता के कारण भोपाल का दूरदर्शन केन्द्र प्रारम्भ नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा ;

(ग) इसका कार्य प्रारम्भ करते समय विभाग की इसे कितने समय में चालू कर देने की योजना थी; और इसके प्रारम्भ किए जाने की लागत और समय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या उपरोक्त केन्द्र के लिए कर्मचारियों की मंजूरी दे दी गई है और वे वहां तैनात भी किये जा चुके हैं परन्तु वे बेकार बैठे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा श्याम) : (क) से (ग) शुरू में भोपाल दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र की स्थापना की परियोजना को जून 1990 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि परियोजना स्थल पर आने वाली कई कठिनाइयों के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप इस पर लगभग 18 महीने का अधिक समय लग गया। परियोजना लागत भी बढ़ गई। लेकिन यह समूची वृद्धि सीधे अधिक समय लगने से संबंधित नहीं है।

वर्तमान संकेतों के अनुसार अब इस परियोजना को चालू वर्ष के अंत तक सेवा के लिये शुरू किये जाने का कार्यक्रम है।

(घ) केन्द्र के लिए पूरे स्टाफ की मंजूरी दे दी गई है और कुछ पद भी भर लिये गये हैं। जो कामिक ड्यूटी पर हाजिर हो गए हैं, उन्हें प्रारम्भिक कार्य पर लगा दिया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास

1625. श्री अजीत जोशी :

कुमारी आलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों को दी गई रियायतों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विकास पर गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा व्यय किए जाने का उपबंध करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र इस समय इस प्रयोजन के लिए कितना प्रतिशत व्यय कर रहा है ?

कामिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा